6. A number of industrial and other projects are being set up as part of the rehabilitation plan, with the objective of providing job opportunities to members of displaced families. These include schemes like textile complex. Vanaspati Plant, leather complex agricultural implement factory etc. The National Range Project will also offer about 500 jobs to the displaced persons. Some families like those of fishermen and landless labourers who due to various reasons may not be rehabilitated in industrial jobs, would be provided special assistance and rehabilitated in self-employment schemes like fishing, dairy, small business and rural transportation. A special fishery complex is being set up for fishermen near Kasafal, south of the Range area. They will be given improved nets and boats and would be provided with required infrastructure like cold storage, godowns etc. A prawn culture facility will also be established.

7. The industrial schemes to be set up under the rehabilitation plan have already been drawn up. Site for various projects is being acquired. Construction of Textile-Complex, at a total cost of about Rs. 19 crores, has been started on a 70-acre plot near Baliapal-town. In principle, clearance has been obtained from IDBI regarding sanction of term-loan for this scheme. A Project report for prawn culture in artificial saline tanks has been prepared. Ground Survey of the Project area has been completed and the work has been entrusted to Brackish Water Fishery Society of Balasore under the technical supervision of Director of Fisheries. Site for Leather Complex has been identified. The construction work is expected to start in the near future and the project is expected to be commissioned in the latter half of 1989.

मानक बैल ड्रोगा

331. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान बैलगाड़ियों की परिवहन क्षमता में सुधार लाने हेतु मानक बैलगाड़ी तैयार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों के राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : विद्यमान बैलगाड़ियों के उन्नत डिजाइनों के विकास के लिए अनेक संगठनों ने अनुसंधान कार्य किया है :

(1) नेशनल रिसर्च डेवेल्पमेंट कारपोरेशन, स्कूल आफ एप्लाइड रिसर्च, मिराज, महाराष्ट्र द्वारा **बलवान** के व्यापारिक नाम के अंतर्गत विकसित सुधरे डिजाइनों वाली बैलगाड़ियों के वाणिज्यीकरण को बढावा देता रहा है। पारंपरिक बैलगाडी की अपेक्षा यह बैलगाड़ी अधिक भार ले जा सकती है और इस के रखरखाव पर कम खर्च आता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध औजारों का प्रयोग होता है। "**बलवान**" बैलगाडी के डिजाइन को अगस्त 1982 में मैसर्स इंदिरा इंडस्ट्रियल वर्क्स, पंढरपुर, महाराष्ट्र को लाइसेंसीकृत किया गया था और अब यह पार्टी इसके उत्पादन में संलग्न है। 1982 में, विशेषकर विकासशील देशों के उपयुक्त आविष्कारों के लिए वर्ल्ड इन्टैलेक्चुअल प्रापर्टी आर्गेनाइजेशन, जेनेवा (संयुक्त राष्ट्र संघ तंत्र का एक अंतः शासकीय संगठन) द्वारा शुरू किया गया पुरुस्कार भी **बलवान** बैलगाडी ने जीता।

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, के नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने पारंपरिक बैलगाडियों के "हब" में एक लचीला तत्व लगाकार इनके कार्य-निष्पादन में सुधार किया है ताकि **बैल-**

गाडियों को कीचड़ में धसने से रोका जा सके ।

(3) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, बंगलौर ने स्थानीय भारवाही पशुओं के विशेष लक्षणों और स्थानीय जलवायु तथा सडक की स्थिति के अनुकूल बैल-गाड़ियों के तीन माडलों का विकास किया है ।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भोपाल स्थित सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरी ने स्वस्नेहक हबों, उचित पहिया संतुलन और उन्नत ब्रेक प्रणालियों का प्रयोग करते हुए गाडियों का विकास किया है ।

(5) कार्टमैन सोसायटी, बंगलौर द्वारा कांउसिल फार एडवान्समेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नालाजी (कैपार्ट) नई दिल्ली के धन से बैलगाडियों के पांच माडलों का विकास किया गया है, इनमें से तीन गाडियों में इस्पात चक्रीय पहिए, इस्पात के ढांचे और ब्रेक लगाने की विधि है । शेष दो में से एक का एल्यूमिनियम का ढांचा है जबकि दूसरे में लकड़ी का प्रयोग हुआ है । के पार्ट इन डिजाइनों के क्षेत्रीय परीक्षणों को करवाने और इनकी प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है ।

Visits of Indian Ports by Warships from various Countries

*332. SHRI KAPIL VERMA:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about thirty warships from 19 countries and some of them carrying nuclear weapons have visited Indian ports during the year 1987;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it indicates any shift in the long-standing policy of Government on foreign warships; and

(d) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) and (b) 29 foreign naval ships visited Indian ports during 1987. These ships came from the following countries:

USSR	9
USA	7
FRANCE	7
THAILAND	2
SWEDEN	1
FRG	1
EGYPT	1
UK	1

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Installation of Low Level Radars along Indo-Pak Borders

*333. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:
SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to install along the entire Indo-Pak border a chain of low level radars;

(b) if so, whether the said low level radar system would effectively detect the movements of aircrafts of the neighbouring countries; and

(c) by when the task of fixing the said system is proposed to be completed?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI K. C. PANT): (a) to (c) Acquisition and utilisation of low level radar systems for the detection of adversary aircraft is a part of the air defence strategy. It will not be in the interest of national security to disclose any further details.